



दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

विनियामक भवन, सी-ब्लॉक शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

वेबसाइट : www.derc.gov.in टेलीफ़ैक्स: 26673608

सार्वजनिक सूचना

निम्नलिखित पर जन सुनवाई

- विद्युत उपयोगिता द्वारा दायर बहु-वर्षीय शुल्क याचिकाएँ
 - ड्राफ्ट डीईआरसी (ग्रिड कनेक्टिड सोलर फोटो वोल्टेक पावर प्रोजेक्ट्स से बिजली की प्राप्ति के लिए शुल्क निर्धारण हेतु कार्यशर्तें) विनियम, 2012, तथा
 - ड्राफ्ट डीईआरसी (नवीकरणीय खरीद बाध्यताएँ तथा नवीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र फ्रेमवर्क क्रियान्वयन) विनियम, 2012
- इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) तथा प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) ने एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए उत्पादन शुल्क के निर्धारण तथा एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु टुइंग-अप के लिए, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ने बहु वर्षीय शुल्क फ्रेमवर्क के अंतर्गत चक्रीय व्यवसाय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एआरआर तथा लागू शुल्क के अनुमोदन हेतु तथा बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), एनडीपीएल / टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए टू-अप के अनुमोदन, टू-अप वर्ष 2011-12 के लिए पुनरीक्षण एवं अस्थाई टू-अप तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वितरण (चक्रीय एवं खुदरा आपूर्ति) व्यवसाय हेतु एमवाईटी याचिका के संबंध में (इन्हें सामूहिक रूप से विद्युत उपयोगिता के रूप में संदर्भित किया गया है) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की है।
 - साझेदारों से आपत्तियाँ / टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30.03.2012 थी जिसे बढ़ाकर 10.04.2012 कर दिया गया था।
 - इसके अलावा, आयोग ने ड्राफ्ट डीईआरसी (ग्रिड कनेक्टिड सोलर फोटो वोल्टेक पावर प्रोजेक्ट्स से बिजली की प्राप्ति के लिए शुल्क निर्धारण हेतु कार्यशर्तें) विनियम, 2012 तथा ड्राफ्ट डीईआरसी (नवीकरणीय खरीद बाध्यताएँ तथा नवीकरण ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क क्रियान्वयन) विनियम, 2012 पर भी साझेदारों से उनकी टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं।
 - दोनों विनियमों पर साझेदारों से आपत्तियाँ / टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तारीख क्रमशः 19.03.2012 तथा 16.03.2012 थी जिसे बढ़ाकर 30.03.2012 कर दिया गया था।
 - आयोग अब उपरोक्त दर्शाई शुल्क याचिकाओं तथा उक्त ड्राफ्ट विनियमों पर निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विनियामक भवन, सी ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017, में जन सुनवाई आयोजित करेगा।

तारीख	समय	श्रेणी
26.04.2012 से 28.04.2012 तक (बृहस्पतिवार से शनिवार) तथा 30.04.2012 (सोमवार)	प्रातः 10.30 बजे से	ड्राफ्ट डीईआरसी (ग्रिड कनेक्टिड सोलर फोटो वोल्टेक पावर प्रोजेक्ट्स से बिजली की प्राप्ति के लिए शुल्क निर्धारण हेतु कार्यशर्तें) विनियम, 2012 तथा ड्राफ्ट डीईआरसी (नवीकरणीय खरीद बाध्यताएँ तथा नवीकरण ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क क्रियान्वयन) विनियम, 2012 पर सुनवाई।
26.04.2012 (बृहस्पतिवार)	प्रातः 10.30 बजे से	वित्तीय वर्ष 2010-11 के टू-अप के लिए, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए पुनरीक्षण एवं अस्थाई टू-अप तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वितरण (चक्रीय एवं खुदरा आपूर्ति) व्यवसाय के संबंध में सभी तीनों डिस्कॉम तथा एनडीएमसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई (घरेलू/रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन)
27.04.2012 (शुक्रवार)	प्रातः 10.30 बजे से	वित्तीय वर्ष 2010-11 के टू-अप के लिए, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए पुनरीक्षण एवं अस्थाई टू-अप तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वितरण (चक्रीय एवं खुदरा आपूर्ति) व्यवसाय के संबंध में सभी तीनों डिस्कॉम तथा एनडीएमसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई (घरेलू / रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ सरकारी निकाय / गैर सरकारी संगठन तथा अन्य)
28.04.2012 (शनिवार)	प्रातः 10.30 बजे से	वित्तीय वर्ष 2010-11 के टू-अप के लिए, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए पुनरीक्षण एवं अस्थाई टू-अप तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वितरण (चक्रीय एवं खुदरा आपूर्ति) व्यवसाय के संबंध में सभी तीनों डिस्कॉम तथा एनडीएमसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई (औद्योगिक/ कर्माश्रित एसोसिएशन तथा अन्य)
30.04.2012 (सोमवार)	प्रातः 10.30 बजे से	एमवाईटी कंट्रोल अवधि वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए उत्पादन शुल्क के निर्धारण तथा एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु टुइंग-अप के लिए आईपीजीसीएल तथा पीपीसीएल और बहु वर्षीय शुल्क फ्रेमवर्क के अंतर्गत चक्रीय व्यवसाय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एआरआर तथा लागू शुल्क के अनुमोदन हेतु डीटीएल द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई।